www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 158 | जौनपुर गुरूवार, 22 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

विभाजन की मांग जम्मू के हित में नही : उमर अब्दुल्ला

कश्मीर, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के विभाजन की राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के दो दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू–कश्मीर की एकता को ष्अपरिवर्तनीयष करार दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग एक बार फिर राज्य को बांटने की मांग कर रहे हैं, वे न केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि जम्मू क्षेत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) का ध्वज लहराता रहेगा, तब तक कोई भी ताकत क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर इस क्षेत्र को विभाजित करने का साहस नहीं करेगी। उमर यहां अपनी पार्टी के दो दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सोमवार से शुरू हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की। पिछले साल 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 'दरबार मूव' को बहाल कर अपना चुनावी वादा पूरा किया। यह एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत सरकार छह–छह महीने जम्मू और श्रीनगर में काम करती है। लगभग 150 साल पहले डोगरा शासकों द्वारा शुरू की गई 'दरबार मूव' प्रथा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जून 2021 में बंद कर दिया था।

उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म पर बयान हेट स्पीच के समान

तमिलनाड, (एजेंसी)। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि 2023 में सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी हेट स्पीच (नफरती भाषण) के दायरे में आती है। हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कड़ी टिप्पणियों में कहा कि द्वारा 100 से ज़्यादा सालों से हिंदू धर्म पर साफ हमला किया गया है, और यह भी कहा कि मंत्री उसी विचारधारा से जुड़े हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जो लोग कथित तौर पर हेट स्पीच देते हैं, उन्हें अक्सर सजा नहीं मिलती। हाई कोर्ट ने कहा, यह साफ है कि पिछले 100 सालों से द्रविड़ कजगम और उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा हिंदू धर्म पर साफ हमला किया गया है, जिससे मंत्री जुड़े हुए हैं। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने मंत्री के भाषण के छिपे हुए मतलब पर सवाल उठाया था। इसमें आगे कहा गया, यह कोर्ट दुख के साथ यह दर्ज करता है कि जो लोग हेट स्पीच देते हैं, उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है।

पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर पूर्वोत्तर की शक्ति को किया नमन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मणिपुर के राज्यपाल, मेघालय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर स्थापना दिवस पर नागरिकों को बधाई दी। मणिपुर के राज्यपाल और मेघालय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर यह पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्रों में इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, विकास की दिशा और उनके लोगों की समर्पण भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को पत्र भेजा और राज्य के निवासियों को राज्य दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेघालय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। खासी, गारो और जैंतिया समुदायों की परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं।ष उन्होंने यह भी कहा कि मेघालय के लोग हमेशा प्रेरणा देने वाले रहे हैं, खासकर उनकी प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयास। प्रधानमंत्री ने 2016 में अपनी शिलांग यात्रा की याद भी ताजा की, जब वह नॉर्थईस्टर्न काउंसिल की बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा, उन्होंने स्वर्गीय पीए संगमा की 10वीं पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके नेतृत्व में मेघालय ने काफी तरक्की की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को भी पत्र भेजा और त्रिपुरा के लोगों को राज्य दिवस की बधाई दी। उन्होंने पत्र में कहा, षत्रिपुरा को समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उत्साही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है।ष प्रधानमंत्री ने 2025 में अपने त्रिपुरा दौरे का उल्लेख किया, जब उन्होंने नवरात्रि के दौरान माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा–अर्चना की और मंदिर के विकास कार्यों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की बढ़ती आर्थिक स्थिति, खासकर राज्य में हुए सुधारों और निवेश में वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के प्रयासों से राज्य ने कई नए अवसरों को जन्म दिया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भी पत्र भेजकर राज्य दिवस की शुभकामनाएं दीं।

द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन राज्यों के उद्यमी और प्रतिभाशाली लोगों ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम के लागू होने के बाद, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972 में पूर्ण राज्य बने थे। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न हैं।" उन्होंने कहा कि इन राज्यों के उद्यमी और प्रतिभाशाली लोगों ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "मैं उनके निवासियों के लिए शांति और समृद्धि से भरे भविष्य की कामना करती हूं।" मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा है। मई 2023 से मणिपुर में इंफाल घाटी के मेइती समुदाय और पहाड़ियों के कुकी–जो समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

दिल्ली ने होली पर कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार मार्च में होली के त्योहार के अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज सुबह हुई बैठक में दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। होली और दीपावली के मौके पर ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की रियायती दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराना, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा था। सूत्रों के अनुसार, राशन कार्ड रखने वाली ईडब्ल्यूएस परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली के दौरान रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है। भाजपा सरकार ने अपने कुछ चुनावी वादे पहले ही पूरे कर दिए हैं, जिनमें दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन और जरूरतमंदों को मात्र पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन खोलना शामिल है।

धर्म, संस्कृति और समाज सेवा पर फोकस : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार से उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वह हरिद्वार और ऋषिकेश में कई महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।इस दौरे को राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह हेल्थकेयर, आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों पर फोकस करता है, जो परंपरा में निहित समग्र विकास पर सरकार के जोर को दिखाता है।अमित शाह ऋषिकेश में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2रू45 बजे, वह स्वर्गाश्रम में गीता भवन पहुंचेंगे, जहां वह मशहूर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका श्कल्याणश के शताब्दी संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित करेंगे।पत्रिका कल्याण ने दशकों से देश और विदेश में भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री से गीता प्रेस के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालने और पिछले 100 सालों में इसकी उपलब्धियों पर बात करने की उम्मीद है। शताब्दी समारोह में उनकी उपस्थिति इस संस्था के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करती है। गुरुवार को अमित शाह हरिद्वार जाएंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10रू00 बजे पतंजलि योगपीठ के महर्षि दयानंद ग्राम में होगा, जहां वह पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे।इसके बाद, सुबह 10रू45 बजे शाह गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचेंगे, जहां वह अखंड ज्योति पर पूजा–अर्चना करेंगे और गायत्री परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। यह दौरा राष्ट्रीय जीवन में गायत्री परिवार के आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री हरिद्वार के बैरागी द्वीप में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्शताब्दी वर्ष समारोह 2026श में भारत और विदेश से भक्तों और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

रायगढ़ पेन स्मार्ट सिटी के लिए फडणवीस ने पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

मुंबई, (एजेंसी)। मुंबई 3.0 के महत्वाकांक्षी मिशन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रायगढ़ पेन स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए दावोस में पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से चार सिंगापुर की कंपनियों के साथ हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान फडणवीस ने 'पीटीआई–भाषा' से कहा कि पांच विदेशी कंपनियों के साथ हुए इन समझौता ज्ञापनों के कारण यहां स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई है और यह अपनी तरह की अनूठी परियोजना होगी जो नवी मुंबई हवाई अड्डे से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पहली बार किसी निजी पार्टी के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर रही है जिसके तहत जमीन निजी पार्टी द्वारा खरीदी जाती है और सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि का विकास कर रही है। उन्होंने कहा, ''वास्तव में यह सबसे बेहतरीन व्यापारिक जिला होगा और सभी अग्रणी व्यवसाय यहीं स्थित होंगे। जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) भी यहीं स्थित होंगे।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके नाम जल्द साझा किए जाएंगे। फडणवीस ने कहा, ''लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वैश्विक समुदाय और निवेशकों के बड़े–बड़े दिग्गजों ने यहां रुचि दिखाई है। उन्होंने हमारे साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो तीसरे मुंबई की शुरुआत करेगा।'' उन्होंने कहा कि यह बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई का एक प्रमुख व्यापारिक जिला) से भी बड़ा होगा। अभी यह लगभग 300 एकड़ में फैला है, लेकिन हम इसे 1,000 एकड़ तक विस्तारित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

कर्नाटक में श्री सिद्धगंगा मठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 21 जनवरी को कर्नाटक जाने वाले हैं। इस दौरान वह तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में श्री शिवकुमार महास्वामीजी के 7वें स्मृति दिवस समारोह में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में श्री शिवकुमार महास्वामीजी के 7वें स्मृति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।वहीं, मंगलवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में स्थित गांधी आश्रम के कस्तूरबा संग्रहालय का दौरा किया, जहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दिल्ली यात्रा के दौरान ठहरे थे। इस दौरे को अत्यंत भावपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर और रसोई की सादगी त्याग, विनम्रता और अटूट दृढ़ संकल्प के उन मूल्यों को सशक्त रूप से दर्शाती है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन किया।उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को ही नई दिल्ली के ऐतिहासिक गांधी आश्रम में हरिजन सेवक संघ का दौरा किया और महादेव देसाई पुस्तकालय विस्तार का उद्घाटन किया। उन्होंने ज्ञान को समाज में स्थायी बदलाव लाने का सबसे मजबूत साधन बताया। उपराष्ट्रपति ने आश्रम के भीतर स्थित कस्तूरबा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने 1930 और 1940 के दशकों में दिल्ली के अपने दौरों के दौरान ठहराव किया था।अपनी यात्रा को बेहद भावनात्मक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आश्रम में घूमते हुए, विशेषकर कस्तूरबा जी के उपयोग किए गए साधारण घर और रसोई को देखकर यह याद दिलाता है कि भारत के नेताओं का जीवन कितना सरल, त्यागपूर्ण और संकल्प से भरा हुआ था। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव देसाई पुस्तकालय विस्तार का उद्घाटन केवल भौतिक जगह के विस्तार का काम नहीं है, बल्कि यह विश्वास की पुनः पुष्टि है कि ज्ञान ही समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा साधन है।

संतों के अपमान के लिए माफी मांगे भाजपा सरकार : अशोक गहलोत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को संतों के इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गहलोत ने कहा, "प्रयागराज जैसी पावन धरा पर, माघ मेले के दौरान पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और उनका अन्न–जल त्यागकर धरने पर बैठना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 'एक्स' पर लिखा, "धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के राज में अगर सर्वोच्च संतों का यह हाल है, तो यह घोर पाप है। सत्ता के अहंकार में प्रशासन द्वारा माफी मांगने के बजाय संत को ही नोटिस थमाना 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि' का प्रमाण है।" गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को संतों के इस अपमान के लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए।

राहुल गांधी का मनरेगा को लेकर सरकार पर निशाना

रायबरेली, (एजेंसी)। मनरेगा को खत्म करके सरकार वीबी–जी–राम–जी नाम से एक नया कानून लेकर आई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गाधी ने मोदी सरकार पर गरीबों के बजाय नौकरशाहों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। मनरेगा के विरोध में कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान चला रही है। मनरेगा पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्ता को केंद्रीकृत करने, इसे नौकरशाही को सौंपने और गरीब नागरिकों को भूखा मरने के लिए छोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मनरेगा का मकसद बेरोजगार ग्रामीणों को पैसे कमाने का जरिया देना था।लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते, वे सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहते हैं और इसे नौकरशाही को सौंपना चाहते हैं। वह गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। एक्ट में सुधार के नाम पर गरीबों का सुरक्षा कवच हटाया गया है। उन्होंने एक्ट से महात्मा गांधी के नाम को हटाने की भी निंदा की।उन्होंने आगे कहा, श्यामला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है. गांधी जी का अपमान किया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमारे गरीब जनता का जो प्रोटेक्शन था, वह हटा दिया गया है। जो डेमोक्रेटिक जड़ है, एक प्रकार से उसको काटा गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन चला रही है जो मजदूरों की मजदूरी और उनके प्रोटेक्शन के लिए है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर जनता की रक्षा नहीं कर रहे हैं और मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर करके ग्रामीण भारत को प्रभावित कर रहे हैं।राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना, जो कांग्रेस ने लागू की थी, उसकी मंशा यह थी कि इसे केंद्र या राज्य सरकार की बजाय पंचायत के माध्यम से चलाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ यह योजना लाई गई थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने मजदूरों और गरीब लोगों की जबरदस्त मदद की। लाखों लोगों को इस योजना ने गरीबी से निकाला। गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें बनीं।

संपादकीय

भारतीय छात्रों को एक और झटका

जिन देशों में पहले भारतीय छात्रों को प्रतिभाशाली एवं शिष्ट समझा जाता था, वहां उनके प्रति नजरिया क्यों बदल गया है? भारतीय छात्र जाकर वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। फिर भी उनकी एंट्री क्यों कठिन होती गई है। विदेश जाकर पढ़ने की हसरत रखने वाले भारतीय छात्रों को एक और झटका लगा है। इस बार खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां भारतीय छात्रों की वीजा अर्जी को उच्चतम जोखिम श्रेणी में डाल दिया गया है। इस फैसले के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसी श्रेणी में रख दिया है, जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पहले से हैं। उन्होंने इसका कारण बताया है– भारतीय छात्रों की शविश्वसनीयता संबंधीय बढ़ा जोखिम। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत में फर्जी डिग्री संबंधी घोटालों के हुए खुलासों की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खूब चर्चा हुई। अब उसका नतीजा सामने आया है। इसके पहले भारतीय छात्रों के लिए कनाडा और ब्रिटेन जाना भी कठिन हुआ है। पिछले वर्ष कनाडा ने भारतीय छात्रों के लिए जारी होने वाले वीजा में 31 प्रतिशत कटौती की। साथ ही जीवन यापन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए वीजा एवं ई–वीजा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अब सिर्फ पीएचडी और रिसर्च छात्र ही अपने जीवनसाथी या बच्चों को ब्रिटेन ले जा सकेंगे। वीजा पाने के लिए आमदनी का पहले से अधिक बड़ा स्रोत उन्हें दिखाना होगा। अमेरिका में तमाम विदेशी छात्रों के लिए हालात जिस तरह बिगड़े हैं, वे अब रोजमर्रा की सुर्खियां हैं। उनसे भी सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय छात्र ही हुए हैं। मुद्दा यह है कि जिन देशों में अभी कुछ वर्ष पहले तक भारतीय छात्रों को प्रतिभाशाली एवं शिष्ट समझा जाता था, वहां उनके प्रति नजरिया क्यों बदल गया है? विदेशी छात्र उन तमाम देशों के शिक्षा क्षेत्र में आय का बड़ा स्रोत हैं। भारतीय छात्र भी वहां जाकर अपना ही पैसा खर्च करते हैं। इसके बावजूद उनकी एंट्री कठिन बना दी गई है। क्या इसका संबंध उन देशों में भारत की बदली छवि से है? या वहां भारतीयों के व्यवहार ने स्थानीय आवाम एवं सरकारों के कान खड़े किए हैं? भारतवासियों को इन प्रश्नों पर गंभीरता से आत्म–निरीक्षण करना चाहिए। कोई भी देश अपने यहां किसे किन शर्तों पर आने देगा, यह तय करना उसका अधिकार है। भारतीयों अगर वहां जाना है, तो उन्हें उनकी कसौटियों पर खरा उतरना होगा।

बड़े पैमाने पर निर्माण, निश्चितता के साथ कार्य पूर्णता

विनायक पाई

पिछले दशक में, भारत के अवसंरचना परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ हैकृऐसा बदलाव, जो केवल परिसंपत्ति निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन और सेवा अदायगी की संरचना तक विस्तारित है। पिछले चरणों की तुलना में इस दौर की विशेषता सिर्फ निवेश के पैमाने या कार्यान्वयन की गति से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि एक सुसंगत, परिणाम–उन्मुख प्रणाली उभर रही है, जो नीतिगत उद्देश्य, संघीय सहयोग और जमीन पर कार्यान्वयन के अनुरूप है। आज, भारत निर्णायक रूप से एक प्लेटफॉर्म–आधारित प्रशासन मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा हैकृ एक ऐसा मॉडल, जो अवसंरचना को अलग–अलग परियोजनाओं के समूह के बजाय एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में देखता है। अलग–अलग परियोजनाओं के बजाय, प्रणाली की सहायता से पैमाने का विस्तार इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है – राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, जो 2014 के लगभग 91,000 किमी से बढ़कर 2024 में 1.46 लाख किमी से अधिक हो गया है। निर्माण की गति में हुई वृद्धि का भी समान महत्व है, जो लगभग 12 किमी प्रति दिन से बढ़कर 34 किमी प्रति दिन से अधिक हो गई है। इस गति को अक्सर एक तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। वास्तव में, यह परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का सहज रूप से समन्वय करने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ बाधाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है और समय पर समाधान किया जाता है। सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, परियोजनाओं के तेजी से पूरे होने का सीधा मतलब है – सामाजिक और आर्थिक लाभों की जल्द प्राप्ति कृ गांव, बाजारों से जुड़ते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक आसान पहुँच की सुविधा मिलती है और आपदा राहत गतिविधि एवं राष्ट्रीय सहनीयता मजबूत होती है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करके औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जवाबदेही को संस्थागत रूप देनारू समीक्षा से समाधान तक इस दशक की एक प्रमुख विशेषता है – समयबद्ध जवाबदेही को संस्थागत रूप देना। प्रगति (सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) की शुरुआत से जटिल, अंतर–मंत्रालयी परियोजनाओं के प्रबंधन को एक नयी दिशा मिली। यहां सबसे महत्वपूर्ण नीति संकेत सांस्कृतिक हैरू विलंब को अब सामान्य नहीं माना जाता और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, बड़े और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजनाएंकृजो कभी लंबे समय तक सुस्त पड़ी रहती थींकृअब पूर्वानुमान और अनुशासन के साथ प्रगति कर रही हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित व विभिन्न स्तरों पर संवाद ने कार्यान्वयन के माहौल को बदल दिया है, विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए जो कई क्षेत्रों में फैली होती हैं। यह मॉडल संवैधानिक भूमिकाओं का सम्मान करता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए सामंजस्य सुनिश्चित करता है। राज्य अब केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि योजना, कार्यान्वयन और परिणाम प्रबंधन में सक्रिय साझेदार हैं। इसका परिणाम है – तेज सहमति निर्माण, कम कानूनी विवाद और जमीन पर सुचारु क्रियान्वयन। उद्योग जगत के दृष्टिकोण से, यह पूर्वानुमान क्षमता कार्यान्वयन जोखिम को कम करती है। नीतिगत दृष्टिकोण से, यह भारत की संघीय कार्यान्वयन क्षमता में विश्वास को मजबूत करती है। विविध प्रारूपों से जुड़ी योजनारू परिसंपत्तियों से नेटवर्क तक भारत की अवसंरचना रणनीति, परिवहन संपर्क से प्रतिस्पर्धा की ओर भी विकसित हो रही है। सड़कों की योजनायें अब केवल अंतिम बिंदुओं के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक लॉजिस्टिक्स और परिवहन इकोसिस्टम के रूप में बनायी जा रही हैं। राजमार्गों का रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी परिवहन के साथ एकीकरणकृजिसका समर्थन राष्ट्रीय योजना रूपरेखाओं, जैसे गति शक्ति द्वारा किया जा रहा हैकृ ने भारत की लंबे समय से मौजूद संरचनात्मक चुनौतियों में से एकरू उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, का समाधान करना शुरू कर दिया है। नीति निर्माताओं के लिए, यह बदलाव एक महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करता हैरू अवसंरचना की दक्षता केवल परिसंपत्ति की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि परिसंपत्तियों के बीच समन्वय से निर्धारित होती है। एकीकृत योजना पुनरावृत्ति को कम करती है।

चीन के साथ मिलकर भारत विरोधी चाल चल रहे बांग्लादेश को ट्रंप ने लगाया डंडा

नीरज

दक्षिण एशिया की राजनीति इस समय दो परतों में खदबदा रही है। एक परत में बांग्लादेश की नीतियां हैं जो धीरे धीरे चीन को भारत की सबसे संवेदनशील भौगोलिक नस के पास लाने की कोशिश करती दिख रही हैं। दूसरी परत में अमेरिका का वह सख्त फैसला है जिसने एक झटके में ढाका को उसकी वास्तविक हैसियत का आईना दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार बांग्लादेश उन 38 देशों की सूची में डाल दिया गया है जिनके नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए अब ठ1ठ2 वीजा पर भारी वीजा बॉन्ड देना पड़ सकता है। यह नियम 21 जनवरी 2026 से लागू होगा। बांग्लादेशी नागरिकों को व्यापार और पर्यटन के लिए अमेरिका जाने से पहले वीजा स्वीकृत होने के बाद पांच हजार, दस हजार या पंद्रह हजार डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। यह राशि किसी स्वचालित नियम से नहीं बल्कि दूतावास के कांसुलर अधिकारी के विवेक से तय होगी। अमेरिकी दूतावास ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कोई भी आवेदक साक्षात्कार से पहले एक भी डॉलर जमा न करे। पहले भुगतान करने से वीजा मिलने की कोई गारंटी नहीं है और तीसरे पक्ष की वेबसाइटें ठगी का जरिया हो सकती हैं। बॉन्ड केवल तभी जमा होगा जब वीजा स्वीकृत हो जाएगा और वह भी अमेरिका सरकार की आधिकारिक भुगतान प्रणाली के जरिये। नियम तोड़ने पर बॉन्ड जब्त हो जाएगा जबकि समय पर अमेरिका छोड़ने या यात्रा ही न करने की स्थिति में यह राशि वापस मिल सकती है। देखा जाये तो यह फैसला केवल तकनीकी वीजा सुधार नहीं है। यह एक सख्त राजनीतिक संकेत है। अमेरिका साफ कर रहा है कि जिन देशों से अवैध प्रवास या नियम उल्लंघन का खतरा अधिक है उन्हें अब आसान पहुंच नहीं मिलेगी। बांग्लादेश को इस सूची में डालना उसके अंतरराष्ट्रीय व्यवहार पर सीधी टिप्पणी है। इसी समय दूसरी तस्वीर और भी चिंताजनक है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास के बीच चीन के राजदूत ने तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया जो भारत के चिकन नेक के बेहद करीब है। यह वही संकरा भूभाग है जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तीस्ता नदी प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के नाम पर चीनी मौजूदगी इस क्षेत्र में केवल विकास सहयोग नहीं कही जा सकती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख सलाहकार पहले ही चीन के साथ गहरी साझेदारी के संकेत दे चुके हैं। बीते वर्षों में चीन ने बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा और अब जल प्रबंधन तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। तीस्ता परियोजना में चीनी तकनीकी आकलन भारत के लिए एक सामरिक चेतावनी है क्योंकि जल संसाधन और सीमावर्ती बुनियादी ढांचा सीधे सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक ओर ढाका बीजिंग को भारत की सबसे संवेदनशील नस के पास लाने की कोशिश करता दिख रहा है तो दूसरी ओर वाशिंगटन उसके लिए दरवाजे सख्त करता जा रहा है। वैसे देखा जाये तो बांग्लादेश इस समय एक खतरनाक भ्रम में जी रहा है। उसे लग रहा है कि वह चीन की गोद में बैठकर क्षेत्रीय ताकत बन जाएगा और भारत पर दबाव बना सकेगा। चिकन नेक के पास चीनी गतिविधियों को न्यूनतम बताना या केवल तकनीकी सहयोग कहना अपने आप को धोखा देना है। यह वही इलाका है जहां एक छोटी–सी अस्थिरता भारत के पूर्वोत्तर को शेष देश से काट सकती है। ऐसे में चीन की मौजूदगी केवल बांग्लादेश की विकास जरूरत नहीं बल्कि एक सुनियोजित भू रणनीतिक चाल है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। यहां हिसाब किताब ताकत और भरोसे का होता है। बांग्लादेश ने यह मान लिया था कि पश्चिम खासकर अमेरिका उसकी हर हरकत को नजरअंदाज करता रहेगा। यहीं सबसे बड़ी भूल हुई। डोनाल्ड ट्रंप की नीति शैली में न तो कूटनीतिक मुलायमियत है और न ही दिखावटी सहानुभूति। वीजा बॉन्ड का फैसला सीधे शब्दों में यह बताता है कि बांग्लादेश अब भरोसेमंद श्रेणी में नहीं रहा। यह फैसला प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। यह बांग्लादेशी मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और व्यापारिक तबके को सीधा आर्थिक झटका है। अमेरिका जाना अब केवल इच्छा नहीं बल्कि क्षमता का प्रश्न बन गया है। यह एक तरह का अनुशासनात्मक कदम है जो बताता है कि नियम तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। सामरिक दृष्टि से यह घटनाक्रम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देता है। अमेरिका का यह रुख बताता है कि वह क्षेत्र में गैर जिम्मेदार व्यवहार को लेकर आंख मूंदे नहीं बैठा है। चीन के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी और आंतरिक अस्थिरता का मिश्रण किसी भी देश को वैश्विक संदेह के घेरे में ला सकता है। बांग्लादेश इसका ताजा उदाहरण है। ढाका को यह समझना होगा कि भारत के साथ टकराव और चीन पर अत्यधिक निर्भरता उसे किसी सुरक्षित भविष्य की ओर नहीं ले जाएगी। उलटे वह ऐसी स्थिति में फंस सकता है जहां न तो पश्चिम भरोसा करेगा और न ही चीन किसी संकट में वास्तविक सहारा बनेगा। इतिहास गवाह है कि बीजिंग अपने हित साधता है स्थायी दोस्ती नहीं निभाता। बहरहाल, वीजा बॉन्ड का यह फैसला केवल कागजी नियम नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शरारतपूर्ण संतुलन साधने की कोशिशें अंततः भारी पड़ती हैं। बांग्लादेश को अपनी औकात और विकल्प दोनों पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। वरना चिकन नेक के पास खेली गई चालें और वाशिंगटन से मिला झटका मिलकर उसे ऐसे मोड़ पर ले जा सकते हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी।

कांग्रेस आलाकमान को कर्नाटक नेतृत्व संकट जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए

कल्याणी शंकर जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व टालमटोल करता दिख रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इससे डीकेएस खेमे में गुस्सा भड़क गया, और समर्थकों ने मांग की कि डीकेएसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पांच राज्यों (तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी) में चुनावनजदीक होने के कारण, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच नेतृत्व की अनसुलझी लड़ाई कांग्रेस की स्थिरता और लोकप्रियता के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। कर्नाटक का राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष में निहित है। बारी–बारी से मुख्यमंत्री बनने की प्रणाली का अनसुलझा सवाल संकट को और गहरा कर रहा है, जिससे कांग्रेस आलाकमान के लिए राज्य को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो गया है।इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत मई 2023 में हुई थी, जब नेतृत्व–साझाकरण समझौते की अटकलें सामने आईं जो अभी भी अनसुलझी हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई।आंतरिक मतभेदों को दूर करने के लिए, कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और शिवकुमार को उनका उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया, इस अफवाह के बीच कि शिवकुमार 2.5 साल बाद पदभार संभालेंगे। 20 नवंबर, 2025 को सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद, शिवकुमार के समर्थकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की, लेकिन सिद्धारमैया ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने पर जोर दिया। डीकेएस ने सार्वजनिक रूप से सीएम सिद्धारमैया को बदलने की किसी भी बात से खुद को दूर कर लिया होगा, लेकिन उनके खेमे ने हार नहीं मानी है। पिछले कुछ हफ्तों से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है।इसका नतीजा लोगों के लिए कुप्रशासन है। भाजपा भी कांग्रेस पर उचित शासन देने में विफल रहने का आरोप लगा रही है। जब मुख्यमंत्री और उनके उपमुख्यमंत्री के बीच खुली लड़ाई होती है, तो पार्टी दो खेमों में बंट जाती है। हाल के घटनाक्रम सिद्धारमैया और शिवकुमार को अलग–अलग लेकिन एक–दूसरे के पूरक कांग्रेस नेताओं के रूप में दिखाते हैं – एक के पास बड़े पैमाने पर मतदाताओं का समर्थन है, दूसरा संकटमोचक है। डीकेएस एक संगठनात्मक व्यक्ति हैं।सिद्धारमैया एक अनुभवी नेता हैं जिनका मतदाताओं से सीधा जुड़ाव है, खासकर अल्पसंख्यतरूहिन्दूलिदवरूओर दलितरू (अहिन्दा)समुदायों (अर्थात् अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों) पर उनकी मजबूत पकड़ है। उन्हें एक सक्षम प्रशासक कहा जाता है। दोनों दावेदार एक–दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस एक विभाजित घर है। सिद्धारमैयाखेमे ने दूसरी जातियों से उपमुख्यमंत्री और एक नए राज्य पार्टी प्रमुख की नियुक्ति की अपनी मांग फिर से उठाई है। शिवकुमार खेमे ने मुख्य मंत्री को बदलने की मांग की है, और कांग्रेस आला कमान को सत्ता की साझेदारी के फॉर्मूले की याद दिलाई है। इस बीच, कांग्रेस आलाकमान फैसला लेने के लिए समय ले रहा है। दोनों में से कोई भी नेता पार्टी को तोड़ सकता है। कोई भी फैसला सोच–समझकर लेना होगा।मैसूरू और दिल्ली में सिद्धारमैया, शिवकुमार और राहुल गांधी के बीच हाल की मुलाकातों ने शिवकुमार की महत्वाकांक्षाओं और सिद्धारमैया की अपनी स्थिति बनाए रखने की इच्छा को उजागर किया। शिवकुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा ऑनलाइन जाहिर की, और सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया। विपक्ष सरकार गिराने का इंतजार कर रहा है। स्थिति तब और खराब हो गयी जब 19 दिसंबर को सिद्धारमैया ने पद पर बने रहने के अपने इरादे की पुष्टि की, और किसी भी कार्यकाल सीमा से इनकार किया। सिद्धारमैया ने भाजपा और जनता दल (सिक्युलर) जेडी(एस) के अविश्वास प्रस्ताव के दावों को खारिज कर दियारू च्च्क्रमशरू केवल 60 और 18 सदस्यों के साथ, वे हमारे 140 को चुनौती नहीं दे सकते। यह प्रयास बेकार है। हम उनके निराधार दावों का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से फिर से बात की। राहुल गांधी के साथ बातचीत का नतीजा अभी भी साफ नहीं है क्योंकि दोनों नेताओं के आगे की बातचीत के लिए दिल्ली आने की उम्मीद है। राहुल गांधी से मिलने के बाददोनों नेताओं ने उस समय कहा कि वे नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। नेतृत्व में देरी ने कांग्रेस आला कमान के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर किया है, जिसमें राहुल गांधी को सिद्धारमैया का पक्ष लेते हुए देखा जा रहा है, जबकि अन्य शिवकुमार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे चल रही अनिश्चितता पर जनता की नाराजगी का खतरा है। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच अनसुलझी लड़ाई अब सीधे तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिरता को खतरे में डाल रही है, जो एक स्पष्ट और निर्णायक समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। दोनों नेता अलग–अलग महत्वाकांक्षाओं से काम करते हैं। सिद्धारमैया का लक्ष्य अपना कार्यकाल पूरा करना, पार्टी पर अधिकार बनाए रखना और अपने नीतिगत एजंडे को जारी रखना है। शिवकुमार अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुख्य मंत्री के रूप में अपनी विरासत स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी आलाकमान जरूरत पड़ने पर कर्नाटक के नेतृत्व विवाद में हस्तक्षेप करेगा। उद्यमी वोक्कालिगाएक्सपो2026 मेंडी.के. शिवकुमार ने पार्टी के फैसले पर भरोसा जतायारू च्च्मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, फिर भी मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं। मुझे भरोसा है कि पार्टी मेरे भविष्य का फैसला करेगी। मैंने राजनीति में कई चुनौतियों का सामना किया है।इस बीच, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व टालमटोल करता दिख रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इससे डीकेएस खेमे में गुस्सा भड़क गया, और समर्थकों ने मांग की कि डीकेएसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पांच राज्यों (तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी) में चुनावनजदीक होने के कारण, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच नेतृत्व की अनसुलझी लड़ाई कांग्रेस की स्थिरता और लोकप्रियता के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। इससे कर्नाटक में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है, और विपक्षी पार्टियों को पार्टी की अंदरूनी फूट का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस आला कमान को अहिंदामतदाताओं और वोक्कालिगा समुदाय के लोगों को अपने साथ बनाए रखना होगा, जिनमें से कुछ शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद में जेडीएसछोड़कर कांग्रेस में आए थे। पहले भी अचानक मुख्यमंत्री हटाए जाने की घटनाओं से उम्मीदों को प्रबंधित करने का दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और सरकार को स्थिर करने और बेंगालुरु के अवसंरचनात्मकचुनौतियों से निपटने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि कर्नाटक पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला आयेगा वह कर्नाटक के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा और राज्य में कांग्रेस पार्टी की स्थिरता भी इसी पर निर्भर करेगी।

भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है चीन

अनिल

चीन का यह रवैया देश के रक्षा मंत्री रहे दिवंगत समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस की उस चेतावनी की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने चीन को श्भारत का दुश्मन नंबर–1श करार दिया था। यह बात करीब ढाई दशक पुरानी है। तब भी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसका नेतृत्व कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार अपमानजनक व्यवहार और धमकी भरे बयान झेलने के बाद अब भारत की नरेन्द्र मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चीन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। चीन के नेताओं से अतीत में किसी मौके पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं की मुलाकातों को लेकर उन्हें अक्सर श्चीन का एजेंटश और श्देशद्रोहीश तक करार देते रहने वाली भाजपा और उसके मार्गदर्शक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने हाल ही में अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से लंबी मुलाकात की है। हैरानी की बात है कि 12 जनवरी को यह मुलाकात हुई, ठीक उसी दिन चीन ने जम्मू–कश्मीर में स्थित शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराते हुए कहा कि –श्इस घाटी में जारी चीन की बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी तरह वैध हैं।श्इस घटनाक्रम से एक बार फिर इस बात की तसदीक होती है कि भारत की सुरक्षा के लिए चीन ही सबसे बड़ा खतरा है और भाजपा व उसकी सरकार अपनी घरेलू राजनीति और दिशाहीन विदेश नीति के चलते चीन को खतरा मानने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति तब है जब पिछले एक दशक के दौरान ही चीन ने कभी लद्दाख तो कभी सिक्किम और कभी अरुणाचल प्रदेश पर न सिर्फ अपना दावा जताया है बल्कि उन इलाकों के नाम बदल कर वहां अपनी सैन्य चौकियां भी कायम की हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए भारत के सैन्य टकराव में भी चीन ने खुल कर पाकिस्तान की मदद की थी।चीन का यह रवैया देश के रक्षा मंत्री रहे दिवंगत समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस की उस चेतावनी की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने चीन को श्भारत का दुश्मन नंबर–1श करार दिया था। यह बात करीब ढाई दशक पुरानी है। तब भी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसका नेतृत्व कर रहे थे। मई, 1998 में वाजपेयी सरकार ने पोखरण–2 परमाणु परीक्षण किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को काली सूची में डाल दिया था। उस विस्फोट के बाद ही एनडीए सरकार के रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने अपने एक चौंकाने वाले बयान में सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक करार दिया था। जार्ज का यह बयान निश्चित ही किन्हीं ठोस सूचनाओं पर आधारित रहा होगा, जो रक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें हासिल हुई होगी। लेकिन उनका यह बयान कई लोगों को रास नहीं आया था। उनके ही कई साथी मंत्रियों ने उनके इस बयान पर नाक–भौंह सिकोड़ी थी। आज की तरह उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे ही नहीं, बल्कि एनडीए की नेतृत्वकारी भाजपा और आरएसएस को भी जॉर्ज का यह बयान नागवार गुजरा था। वामपंथी दलों को तो स्वाभाविक रूप से जॉर्ज की यह साफगोई नहीं ही सुहा सकती थी, सो नहीं सुहाई थी।यह दिलचस्प था कि संघ और वामपंथियों के रूप में दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाली ताकतें इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे दोनों ने अलग–अलग कारणों से 1942 में श्भारत छोड़ोश आंदोलन का विरोध किया था। जॉर्ज के इस बयान के विरोध के पीछे भी दोनों की प्रेरणाएं अलग–अलग थीं। संघी कुनबा जहां अपनी चिर–परिचित मुस्लिम विरोधी ग्रंथि के चलते पाकिस्तान के अलावा किसी और देश को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मान सकता था, वहीं वामपंथी दल चीन के साथ अपने वैचारिक बिरादराना रिश्तों के चलते जॉर्ज के बयान को खारिज कर रहे थे। कई तथाकथित रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों समेत मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इसके लिए जॉर्ज की काफी लानत–मलानत की थी।जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन चीन को लेकर उनका आकलन समय की कसौटी पर बीते ढाई दशकों के दौरान और खास कर पिछले एक दशक में ही कई बार सही साबित हुआ है। इस समय भी चीन का रवैया जॉर्ज के कहे की तसदीक कर रहा है। वैसे न तो चीनी खतरा भारत के लिए नया है और न ही उससे आगाह करने वाले जॉर्ज अकेले राजनेता रहे। 2017 में चीन की सेना जब डोकलाम में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी, तब संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने भी अपने अनुभव के आधार पर चीनी खतरे के प्रति सरकार को आगाह किया था। इस मसले पर लोकसभा में बहस के दौरान मुलायम सिंह ने दो टूक कहा था कि भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है और सरकार उसे हल्के में न ले।दरअसल, चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था, तभी से वह भारत के लिए खतरा बना हुआ है। देश को सबसे पहले इस खतरे की चेतावनी राममनोहर लोहिया ने दी थी। तिब्बत पर चीनी हमले को उन्होंने श्शिशु हत्याश्य करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वे तिब्बत पर चीनी कब्जे को मान्यता न दे, लेकिन नेहरू ने लोहिया की सलाह मानने के बजाय चीनी नेता चाऊ एन लाई से अपनी दोस्ती को तरजीह देते हुए तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग मानने में जरा भी देरी नहीं की। यह वह समय था जब भारत को आजाद हुए महज 11 वर्ष हुए थे और माओ की सरपरस्ती में चीन की लाल क्रांति भी नौ साल पुरानी ही थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू तब समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे जिसमें चीन से युद्ध की कोई जगह नहीं थी। उधर माओ को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना था कि साम्यवादी कट्टरता के मामले में वे लेनिन और स्टालिन से भी आगे हैं। तिब्बत पर कब्जा उनके इसी मंसूबे का नतीजा था। इतना सब होने के बावजूद लगभग एक दशक तक भारत–चीन के बीच राजनयिक रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन 1960 का दशक शुरू होते–होते चीनी नेतृत्व के विस्तारवादी इरादों ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी और भारत के साथ उसके रिश्ते शीतकाल में प्रवेश कर गए। तिब्बत जब तक आजाद देश था, तब तक चीन और भारत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था, क्योंकि तब भारतीय सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलती थीं। मगर चीन द्वारा तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद वहां तैनात चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगी। उन्हीं दिनों चीन की ओर से जारी किए गए नक्शों से भारत को पहली बार झटका लगा। उन नक्शों में भारत के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही भूटान के भी कुछ हिस्से को चीन का भू–भाग बताया गया था। चूंकि इसी दौरान भारत यात्रा पर आए चाऊ एन लाई नई दिल्ली में पंडित नेहरू के साथ श्हिंदी–चीनी, भाई–भाईश का नारा लगाते हुए शांति के कबूतर उड़ा चुके थे, भावुक भारतीय नेतृत्व को भरोसा था ।

केजीएमयू के टॉमा सेंटर में भर्ती होते ही घायल के खाते में आएंगे 10 हजार रुपये

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने वाले मरीज और घायलों को शुरुआती 24 घंटे निशुल्क इलाज देने का खाका खींच लिया गया है। इसके तहत परचे के साथ ही मरीज का एक वर्चुअल खाता बनाकर उसमें 10 हजार रुपये डाले जाएंगे। इसी राशि से जांच और दवाओं की रसीद काटी जाएगी। जरूरत पड़ने पर धनराशि दोबारा भी डाली जाएगी। ट्रॉमा सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रेमराज ने बताया कि शुरुआती 24 घंटे निशुल्क इलाज की सुविधा 26 जनवरी से पहले ही शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए कई स्तर पर तैयारी की गई है। परचा बनाने और रसीद काटने

वाले कर्मियों को नई व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। मरीज या घायल के खाते में धनराशि डालने की जिम्मेदारी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की होगी। 10 हजार रुपये की धनराशि जांच और दवाओं के खर्च के आकलन के आधार पर तय की गई है। सामान्य रूप से सभी जांच और शुरुआती दवाओं का खर्च 10 हजार रुपये तक ही होता है। अगर यह धनराशि कम पड़ेगी तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर दोबारा धनराशि डाल देगा। अनुमान है कि नई व्यवस्था से संस्थान पर हर महीने दो से तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। फिलहाल सिर्फ जांच और दवाओं की निशुल्क व्यवस्था होगी। इंप्लांट आदि का खर्च निशुल्क इलाज में शामिल नहीं किया जाएगा। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में पहले 24 घंटे निशुल्क इलाज की व्यवस्थान होने का मुद्दा अमर उजाला ने 26 अगस्त, 2025 के अंक में उठाया था। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेकर समिति बनाई। समिति ने निशुल्क इलाज पर आने वाले खर्च का आकलन करने के साथ ही इसका पूरा खाका तैयार किया। अब यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। राजधानी के अन्य दो चिकित्सा संस्थान डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी और संजय गांधी पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में शुरुआती 24 घंटे पूरी तरह से निशुल्क इलाज की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

हाईकोर्ट के आदेश से खुला सीज मदरसा

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के श्रावस्ती में एक गैर–मान्यता प्राप्त मदरसे की सील हटाने के आदेश के बाद प्रदेश के ऐसे अन्य मदरसों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि, अब भी यह सवाल बरकरार है कि क्या नेपाल सीमा के नजदीकी जिलों समेत प्रदेशभर में इसी आधार पर बंद किए गए सैकड़ों मदरसों से सील हट पाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश में करीब 16460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। मदरसा बोर्ड ने साल 2017 से नए मदरसों को मान्यता पर अघोषित रोक लगा रखी है। इस पर बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने शासन को वर्ष 2022 में मानक पूरे करने वाले मदरसों को मान्यता देने के लिए सर्वे कराने का प्रस्ताव भेजा था। शासन के सर्वे में प्रदेश में 8449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और मकतब सामने आए। साल 2024 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने सर्वे रिपोर्ट से 4204 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिह्नित कर जिलास्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का पत्र जिलाधिकारियों को भेजा। इसके बाद जिलों में बनी कमेटियों ने मदरसों का संचालन बंद करने और गैर मुस्लिम बच्चों की सूची उपलब्ध कराने की नोटिस देकर कार्रवाई शुरू कर दी। नेपाल के सीमावर्ती जिलों के मदरसों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई थी। एक निजी सर्वे के मुताबिक श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर में ही 500 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए थे। कई जिलों में मदरसे ध्वस्त भी किए गए थे। मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य हाजी दीवान साहेब जमां खां के मुताबिक, मानक पूरे करने वाले मदरसों को मान्यता देने के बजाय बंद करना न्यायसंगत नहीं था। शिक्षण संस्थानों को संचालन के बाद मान्यता दी जाती है।

संक्षिप्त खबरें

'ग्रामीण पत्रकार एसोसिशन के पत्रकारों ने शोक सभा आयोजित करके दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली––(हरदोई)' ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन शाहाबाद द्वारा एक शोकसभा का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार सैय्यद रईस अली के मो० गिगीयानी स्थित एक स्कूल में किया गया।अभी चंद दिनों पूर्व ही वरिष्ठ पत्रकार व ग्रा०प०ए० के लखनऊ मंडल अध्यक्ष अखिलेश सिंह,वरिष्ठ पत्रकार प्रियंक दीक्षित और वरिष्ठ पत्रकार अभिनव द्विवेदी की माता जी का आकस्मिक निधन हो गया है असमय मृत्यु को प्राप्त तीनों दिवंगत आत्माओं को उपस्थित पत्रकारों ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।शोक व्यक्त करते हुए

वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मिश्रा ने कहा कि अखिलेश सिंह एक निर्भीक,निष्पक्ष और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार थे।संगठन के महामंत्री वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक ने अपने संगठन के मंडल अध्यक्ष दिवंगत पत्रकार अखिलेश सिंह को सज्जन,विनम्र एवं शालीन व्यक्तित्व का धनी बताते हुए अपने पत्रकार एसोसिएशन की अपूर्णीय क्षति बताया।उन्होंने मिलनसार व्यक्तित्व वाले प्रियंक दीक्षित और वरिष्ठ पत्रकार अभिनव द्विवेदी की माता जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इसे पत्रकार परिवार का गहरा दुख बताया।एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश प्रसाद मिश्रा,प्रांतीय सदस्य सैय्यद रईस अली व अशरफ अली ने भी कहा कि दिवंगत दोनों पत्रकारों ने अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में सदैव सच्चाई और जनहित को प्राथमिकता दी।अंत में उपस्थित पत्रकारों में दिनेश प्रसाद मिश्रा,कमलेश मिश्रा,आलोक पाठक,सैय्यद रईस अली,अशरफ अली,प्रभाकर त्रिपाठी,अतुल मिश्रा,राम किशोर राठौर,दिनेश कुमार मिश्रा,अखिलेश बाथम,महेंद्र गुप्त,कमलेश त्रिवेदी,इजहार खा,रोहित गुप्ता,आशीष अवस्थी,अनिल शर्मा,गुड्डू वर्मा,कमलेश कुमार दो मिनट का मौन धारण करके शोक संतृप्त परिवारों को सहनशक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए।

आयकर के घूसखोर अफसर को 7 साल कैद की सजा, मांगे थे 10 लाख रुपये

लखनऊ, (संवाददाता)। कर निर्धारण के लिए व्यापारी से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने में आयकर विभाग के अधिकारी निरंजन कुमार को दोषी ठहराया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने उसे सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि मेसर्स प्रगति कॉलोनाइजर्स कंपनी के निदेशक जयकेश त्रिपाठी की ओर से 27 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

राष्ट्रवाद व लोकतंत्र की आधारशिला है हिंदी

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी प्रेस क्लब में मंगलवार को शब्द सरिता की ओर से राष्ट्रवाद व भाषायी संप्रभुता का संवैधानिक यथार्थ विषयक गोष्ठी एवं सम्मान समारोह हुआ। शब्द सरिता के संरक्षक व मुख्य वक्ता पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडेय ने बताया कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की आधारशिला हिंदी ही है। भाषाई संप्रभुता संपन्न और संवैधानिक यथार्थ की कसौटी पर ही हिंदी पूर्ण है। संस्थापक अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि हिंदी एक मात्र भाषा है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। कार्यक्रम में शशि गुप्ता, अल्का, अशोक, उमाशंकर, जमुना, नारायण गुप्ता एवं उमा शंकर तिवारी को सम्मानित किया गया।

प्रयोग परामर्श हेल्पलाइन से दूर होंगी शंकाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेश पर राजधानी सहित लखनऊ मंडल में 24 जनवरी से इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस दौरान विद्यार्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) लखनऊ कार्यालय में प्रयोग परामर्श हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से विज्ञान वर्ग के विशेषज्ञ छात्रों को आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन देंगे। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि एक फरवरी तक यूपी बोर्ड कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 941566467 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन 23 जनवरी से सक्रिय की जाएगी। हेल्पलाइन के जरिये इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक कार्य से जुड़े टिप्स दिए जाएंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के तरीके, मौखिकी की तैयारी और बेहतर प्रायोगिक प्रस्तुति जैसे बिंदुओं पर भी मार्गदर्शन मिलेगा। हेल्पलाइन पर रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में शिप्रा श्रीवास्तव और स्वयं डॉ. दिनेश कुमार, भौतिक विज्ञान के लिए डॉ. अरविंद कुमार वर्मा तथा जीव विज्ञान के लिए दीप्ति विश्वकर्मा उपलब्ध रहेंगी। हेल्पलाइन आयोजन के अभिलेखीकरण का कार्य गणित विषय के शिक्षक पवन कुमार तिवारी करेंगे।

प्रमोशन के लिए शिक्षक 25 तक समर्थ पोर्टल पर भरें ब्योरा

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन करियर एडवांसमेंट योजना (कैस) के तहत प्रमोशन पाने के लिए 25 जनवरी तक अपना मूल्यांकन स्वतरू करके समर्थ पोर्टल पर ब्योरा अपलोड करना होगा। इसके बाद विजिलेंस ऑफिसर की ओर से अपलोड ब्योरे के आधार पर वेरिफिकेशन होगा। पात्रता पाए जाने पर ही प्रमोशन होगा। इस संबंध में कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने मंगलवार को बैठक कर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए। विश्वविद्यालय में यूजीसी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठ आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों का प्रमोशन होना बाकी है। ऐसे में इसका एजेंडा तीन दिनों के भीतर कुलसचिव को भेजने के लिए कहा गया। बैठक

में कुलसचिव के निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी शिक्षकों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए, जिन्होंने अब तक वरिष्ठ आचार्य पदोन्नति के लिए आवेदन नहीं किया है वह अपना ब्योरा समर्थ पोर्टल पर अपलोड करें। विश्वविद्यालय में अब तक विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति न होने से कुलपति ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही कुलसचिव को निर्देशित किया कि विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। बैठक में ई–ऑफिस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कुलपति ने कर्मचारियों कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी विद्या परिषद, वित्त समिति व कार्य परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रकरणों से जुड़ी समितिया ब्योरे दें साथ ही काम में तेजी लाएं।

संक्षिप्त खबरें

तीखी धूप से राजधानी में फीकी पड़ी ठंड

लखनऊ, (संवाददाता)। मौसम के बदले मिजाज ने राजधानी में मंगलवार को दिन में ठंड का डर दूर भगा दिया। सुबह कोहरे का असर भी मामूली रहा। तीखी धूप से ठंड पूरी तरह से फीकी पड़ गई। दोपहर में धूप के तेवर से लोगों के गर्म कपड़े भी उतरवा दिए। मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव से कोहरे में कमी आने के साथ ठंड से भी राहत मिली है। यह राहत आगे भी जारी रह सकती है। आगामी 24 घंटों में तापमान में थोड़ी गिरावट के उपरांत उत्तरोत्तर दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 23 और 24 जनवरी को बारिश के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवा के दिशा परिवर्तन और आसमान साफ होने से सोमवार रात न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आगामी 24 घंटों तक यह गिरावट जारी रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में मामूली क्रमिक गिरावट के बावजूद सामान्य से ऊपर ही बने रहने के आसार हैं। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान में एक डिग्री की कमी के साथ 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की कमी के साथ 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा।

जन औषधि केंद्रों पर अब और सस्ती मिलेंगी दवाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। सरकारी अस्पतालों में संचालित जन औषधि केंद्रों पर अब मरीजों को और भी सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद नए प्रिंट रेट की दवाओं की आपूर्ति शुरू हो गई है, जिससे हर दवा पर दो से चार रुपये की कमी आई है। राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और सीएचसी में खुले जन औषधि केंद्रों पर मरीजों को बाजार भाव से 40 से 70 फीसदी छूट पर दवाएं मिलती हैं। सरकार ने सितंबर में दवाओं पर लगने वाली जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच फीसदी कर दी थी। इस घटी दर की दवाएं बाजार में अब आ रही हैं। जन औषधि केंद्र के प्रभारियों का कहना है कि नए प्रिंट रेट की दवाएं अब आने लगी हैं। इससे बीपी, शुगर, किडनी व सूजन जैसी दवाओं के दाम पहले से कम हो गए हैं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है।

किराये के मकान की समस्या ने खूब हंसाया

लखनऊ, (संवाददाता)। देवसु थियेटर आर्ट्स सोसाइटी की ओर से मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में 60 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत तैयार की गई प्रस्तुति खुदा खैर करे... नाटक का मंचन किया गया। आत्माराम सामंत के मूल लेखन का श्रीधर जोशी ने नाट्य रूपांतरण किया और अशोक लाल ने निर्देशन किया। नाटक में किराये के मकान की समस्या को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। नाटक का नायक शराफत हुसैन जो कि वास्तव में एक विवाहित है और दूसरे शहर में नौकरी करने आया है। उस शहर में किराये का मकान ढूंढ़ते हुए एक ऐसा मकान किराये पर लेता है जहां का मकान मालिक केवल कुंवारों को मकान देता है। शराफत खुद को कुंवारा बताकर और अपनी बीवी को बहन बताकर मकान किराये पर ले लेता है। मकान मालिक अपनी बेटी पम्मी की शादी शराफत से कराकर उसे घर जमाई बनाना चाहता है। कई दिलचस्प घटनाओं के बाद शमीम के अब्बू (पिता) मीर साहब वहां आ धमकते है। अंत में नाटकीय परिस्थितियों में घटना का रहस्योद्घाटन होता है। सौरभ सिंह, अर्पित श्रीवास्तव, तारिक इकबाल, दीपा यादव, आनंद प्रकाश शर्मा, खुशी और मोहित यादव ने शानदार अभिनय कर दर्शकों को खूब हंसाया।

लखनऊ फॉल्कंस ने जीती फुटबॉल प्रतियोगिता

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ फॉल्कंस ने बिग ब्ल्यू को रोमांचक मुकाबले में 1–0 से हराते हुए सतवंत सिंह और रवींद्र पाल मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली। मध्यांतर तक स्कोर गोलरहित बराबर रहा। चौक स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कांटे का संघर्ष देखने को मिला, जिसका मौजूदा दर्शकों ने लुफ उठाया। इस दौरान कई मूव देखने को मिले, लेकिन गोल बदलने में कोई भी टीम सफलता हासिल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ के शुरू होते ही लखनऊ फॉल्कंस ने आक्रामक रुख अपनाया और हमलों की झड़ी लगा दी। खेल के 60वें मिनट में टीम के अभिषेक ने साथी खिलाड़ी के पास को गोल में बदलते हुए टीम को 1–0 से बढ़त दिलाई। एक गोल से पिछड़ने के बाद बिग ब्ल्यू ने वापसी के लिए कई मूव बनाए, लेकिन लखनऊ फॉल्कंस की सजग रक्षापंक्ति ने उनके सभी प्रयास व्यर्थ कर दिए। इस दौरान बिग ब्ल्यू की अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने कुछ मौके गवाएं। इसका खामियाजा टीम को हार के रूप में चुकाना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन पर एसआर ग्रुप के निदेशक पीयूष चौहान ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। मौके पर देवेंद्र सिंह, सपन राय, अनुराग मिश्रा, कन्हैया लाल समेत बड़ी संख्या में पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई।

सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की 100 करोड़ की बेनामी भूमि हुई सरकारी

लखनऊ, (संवाददाता)। जौनपुर से सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी देशराज सिंह की कानपुर रोड स्थित 100 करोड़ रुपये कीमत की भूमि अब सरकारी हो गई है। इसे आयकर विभाग ने मार्च, 2023 में बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत जब्त किया था। विभाग के आदेश को नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने सही पाया है। अब आयकर विभाग इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के बाद नीलाम कर सकता है। आयकर विभाग को इस संपत्ति के बारे में देशराज सिंह के कानपुर स्थित आवास पर मई, 2022 में मारे गए छापे के दौरान सुराग मिला था। यह छापा आयकर विभाग के राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की बेनामी संपत्तियों का पता लगाने वाले श्ऑपरेशन बाबू साहब–2श अभियान के तहत मारा गया था। जांच में सामने आया था कि पहले यह संपत्ति एक कंपनी के नाम थी, जिसे बाद में बाबू सिंह के करीबी देशराज को कागजों पर बेचा गया था। जबकि संपत्ति पर कब्जा बाबू सिंह का ही पाया गया था। बंथरा इलाके के जुनाबगंज स्थित पांच सितारा होटल के सामने 1.6670 हेक्टेयर भूमि की इस जमीन की खरीद–फरोख्त फर्जी तरीके से की गई थी। कागज में दिखावे मात्र के लिए चेक नंबरों का जिक्र किया गया था। दरअसल, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने सरोजनीनगर में उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक देवेंद्र पाल की कार से 30 लाख रुपये की नकदी बरामद की थी। इसके बाद लखनऊ, दिल्ली व गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापे में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के दो करीबियों कानपुर के राजू चौहान व देशराज सिंह कुशवाहा के बारे में पता चलाए जो प्रॉपर्टी डीलर थे।

नवाबी दौर से स्वतंत्रता संग्राम तक की साक्षी रही रिफा-ए-आम इमारत अब बदहाल

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर के गोलागंज इलाके में सिटी रेलवे स्टेशन के करीब एक ऐतिहासिक इमारत 'रिफा–ए–आम' जो कभी अवध की बौद्धिक संपदा कही जाती थी, आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। भारतीय गणतंत्र की गवाह यह 165 साल से ज्यादा पुरानी इमारत आज बदहाल है। शायर मुशीर झंझानवी का एक शेर इस ऐतिहासिक इमारत पर बिल्कुल सटीक बैठता है– कांटा समझ के मुझसे न दामन बचाइए, गुजरी हुई बहार की एक यादगार हूं..। नवाबी दौर से स्वतंत्रता संग्राम तक और आजाद भारत की शान रही इस इमारत का ज्यादातर हिस्सा गिर चुका है। यह इमारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठकों के साथ प्रगतिशील लेखक संघ की पहली बैठक की भी साक्षी रही है। अवध के रजवाड़ों ने मिलकर इसी इमारत में अंग्रेजों से बदला लेने के लिए रिफा–ए–आम क्लब की स्थापना की थी। यह क्लब अपनी स्थापना के पीछे एक बेहद रोचक कहानी समेटे हुए है। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में लखनऊ और आसपास के रजवाड़ों को कैंट के एमबी क्लब और हजरतगंज स्थित रिंक थियेटर समेत अन्य क्लबों में

प्रवेश से रोकने के लिए अंग्रेजों ने 'इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड' का बोर्ड लगा दिया था। इस अपमान से आहत महमूदाबाद एस्टेट और मनकापुर एस्टेट समेत कई राजाओं ने मिलकर रिफा–ए–आम इमारत में क्लब की स्थापना की। यह क्लब न केवल रजवाड़ों की आरामगाह था, बल्कि खेल, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बना। यहां कुछ साल पहले तक बैडमिंटन कोर्ट था। साहित्यकारों की बैठकी हुआ करती थी। रवि भट्ट ने बताया कि इस इमारत को किसने बनवाया, इस पर मतभेद हैं लेकिन यह सच है कि इसका निर्माण नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ से जाने के बाद ही करीब 1860 के आसपास हुआ था। संभवतरू इस इमारत को अवध के रजवाड़ों ने मिलकर ही बनवाया होगा। रिफा–ए–आम क्लब का इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद से भी गहराई से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहीं पर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच वह ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ इतिहासकार यहां 1920 में महात्मा गांधी के आने की भी पुष्टि करते हैं। कहा जाता है कि पटेल और नेहरू ने भी 1922 को यहां स्वदेशी आंदोलन तेज करने को लेकर भाषण दिया था। हालांकि मशहूर दास्तानगो हिमांशु बाजपेई का कहना है कि इस इमारत में लखनऊ समझौता नहीं हुआ था, हां यह जरूर है कि प्रगतिशील लेखक संघ की पहली बैठक 1936 में यहीं पर हुई थी जिसमें मुंशी प्रेमचंद समेत हिंदी–उर्दू के देश के बड़े लेखक शामिल हुए थे। मुंशी प्रेमचंद ने अपने भाषण में यहां कहा था कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसका काफी हिस्सा गिर चुका है। जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और यहां आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिए केवल गार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके चारों ओर बाउंड्रीवॉल करवा दी है। एलडीए प्रशासन ने पिछले साल यहां से अवैध कब्जे हटवाए थे और यह आश्वासन भी दिया था कि निकट भविष्य में क्लब का विकास कार्य शुरू किया जाएगा और इसे एक नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर का खोया गौरव वापस लौट सके। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इंटेक इस इमारत में सर्वे का काम कर रहा है और इस इमारत को संवारने के लिए प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहा है। उम्मीद है जल्द इमारत का सुंदरीकरण होगा।

बिलरियागंज स्थानीय बाजार के मूल निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी हरिहर प्रसाद जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु से शोक की लहर : मृतक आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का किया गया आयोजन

ब्यूरो चीफ राजकुमार जायसवाल

आजमगढ़रूबिलरियागंज स्थानीय बाजार के मूल निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी हरिहर प्रसाद जायसवाल की बीते 14 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना में मोहन नगर गाजियाबाद के पास निध न हो गया। जिसको लेकर बृहस्पतिवार को उनके आवास बिलरियागंज पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अधिक संख्या में लोगो ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार बिलरियागंज बाजार निवासी हरिहर प्रसाद जायसवाल की मोहन नगर गाजियाबाद के पास दूकान है ।वही बीते 14 जनवरी को दूकान जाते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जिसको लेकर बाजार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमे लोगो ने श्रद्धांजलि अर्पित किया । इस दुःख की घड़ी में ईश्वर से उनके परिवार को सहनशक्ति प्रदान करने की प्रार्थना किया। इस मौके पर पूर्व ब्लाक प्रमुख मुखराम यादव, जगदम्बा जायसवाल ,राजेश जायसवाल, चन्द्रभान यादव ,अशोक जायसवाल ,डॉ वीरेंद्र प्रजापति, मोहन जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, बलराज यादव , शाहआलम किसान यादव, पिन्टू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर दी गई श्रद्धांजलि

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर गुप्तार घाट स्थित(गुमनामी बाबा) सुभाष चंद्र बोस की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि कर किया उन्हें नमन, भाजपा नेता दिनेश जायसवाल एवं अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने संयुक्त रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वैसे तो यह जांच का विषय है लेकिन हम सभी का व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आज उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी उन्हें नमन कर रहे हैं ,नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना लंबा समय फैजाबाद जनपद जो कि अब अयोध्या है में बिताया है सिविल लाइन स्थित राम भवन में उनका लंबा समय यहां व्यतीत हुआ है 16 सितंबर 1985 को उनका निधन हुआ था , आज उनकी जयंती के अवसर पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम विकसित भारत की नीव रख सकते हैं ,विमलेश यादव, पंडित निषाद और सिद्धार्थ जी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

सपा महिला जिलाअध्यक्ष सरोज यादव ने किया परिवार सहित किए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन पूजन

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना हुआ है।इसी क्रम में सामाजिक रूप से सक्रिय समाजवादी पार्टी महिला सभा जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने अपने परिवार सहित भव्य श्रीराम मंदिर में दर्शन–पूजन किया।दर्शन के उपरांत सरोज यादव ने कहा कि "श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करना केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभूति है।यह क्षण हमारे पूरे परिवार के लिए जीवन भर यादगार रहेगा।उन्होंने कहा कि भगवान

श्रीराम भारतीय संस्कृति, मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं, और उनके दर्शन करने से मन को अद्भुत शांति और ऊर्जा प्राप्त हुई।परिवार के सभी सदस्यों ने श्रद्धा भाव से पूजा–अर्चना की और देश व समाज की सुख–समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर की भव्यता, स्वच्छता और व्यवस्थाओं की भी सराहना की गई।यह दर्शन कार्यक्रम धार्मिक आस्था, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का सशक्त संदेश देता है।

राजस्व कर्मचारी के निधन हुई पर शोक सभा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। गुरुवार को जिलाधिकारी दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में शाहगंज तहसील के सहायक राजस्व लेखाकार अखिलेश सिंह के निध न पर शोकसभा का आयोजन किया गया । शोकसभा में अपर जिलाधि ाकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, अपर जिलाधिकारी भू–राजस्व अजय अम्बष्ट, विजय प्रताप सिंह अध्यक्ष कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, राजीव श्रीवास्तव जिलामंत्री एवं कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में

दो मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शैलेन्द्र प्रताप सिंह, अरविंद कुमार सिंह, मेंहदी रजा, प्रमोद कुमार यादव, लक्ष्मीकांत यादव, आशीष कुमार त्रिपाठी, आशीष कुमार श्रीवास्तव, राजेश यादव, यतेन्द्र यादव, उधव प्रसाद, त्रिलोकी नाथ सिंह, फरहान हैदर, पवन कुमार मौर्या, संतोष दयाल, रिंकू कुमार, हर्षित श्रीवास्तव, विनोद सोनकर, प्रेम वर्मा, नीरज यादव, आनंद कुमार सिंह, कुसुम यादव, पुष्पा श्रीवास्तव, अजीत कुमार, चन्द्र प्रकाश शुक्ला, आयुष कुमार सिंह, अमीर हमजा, विजय कुमार विन्द आदि उपस्थित रहे।

सीओ सिटी व अन्य अधिकारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन व शहर मे चलाया चेकिंग अभियान

अयोध्या।बुधवार को देर शाम कैंट रेलवे स्टेशन पर 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस व माघ मेला की सुरक्षा को लेकर सीओ सीओ सिटी श्रेयांश त्रिपाठी शहर क्षेत्रो के अलावा रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन सभी जगह पर मौजूद रेल यात्रियों के सामानो को भी खंगाला।उन्होंने डाग स्क्वाड टीम के अलावा आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस के साथ स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म , सर्कुलेटिंग व पार्किंग एरिया इत्यादि में सघन चेकिंग अभियान चलाया।इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही,प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन समर बहादुर सिंह,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्विनी कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम तहत पशुओं के सातवें चरण के टीकाकरण की वैन को मंत्री गिरीश चंद्र ने दिखाया हरि झंडी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका–मुंहपका रोग (एफएमडी) के सातवें चरण का टीकाकरण अभियान गुरुवार को प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव और जिलाधि ाकारी डॉ. दिनेश चंद्र एडीएम अजय अंबष्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर से पशुपालन विभाग के 14 बहुउद्देशीय वाहन, 4 एम्बुलेंस और 4 सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान 22 जनवरी से 10 मार्च तक संचालित होगा। जिले को इस अभियान हेतु 6,00,550 वैक्सीन खुराकें प्राप्त हुई हैं, जबकि कुल 6,32,664 पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। इनमें 2,95,060 गौवंशीय और 3,37,604 महिषवंशीय पशु सम्मिलित हैं।इस टीकाकरण अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जनपद के 21 विकास खंडों में कुल 43 टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में एक उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारीध पशुचिकित्साधिकारी, एक पशुधन प्रसार अधिकारी तथा दो से तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीधपैरावेट शामिल हैं। जिले की 1740 ग्राम पंचायतों में लगभग 2,00,000 पशुपालकों के पशुओं को टीका लगाया जाएगा। खुरपका–मुंहपका रोग एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित बीमारी है, जो संक्रमित पशुओं से स्वस्थ पशुओं में तीव्र गति से फैलती है। यह रोग मुख्य रूप से गोवंश और महिषवंश को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षणों में पशुओं को तेज बुखार आना, भोजन त्याग देना, दूध उत्पादन में कमी, मुंह और खुरों में छाले पड़ना तथा लंगड़ाना सम्मिलित हैं।इस गंभीर रोग के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु टीकाकरण ही एकमात्र प्रभावी उपाय है। पशुपालकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाकर उन्हें इस बीमारी से सुरक्षित रखें।

केंद्र और प्रदेश सरकारें 'SIR' की आड़ में NRC लागू करने की साजिश रच रही हैं : राममूर्ति वर्मा

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर । यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा गुरुवार को महान समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई। नगर के होटल रिवर व्यू में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके समाजवादी विचारों पर चर्चा की गई और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। पुण्यतिथि कार्यक्रम के बाद शैप्स कार्य की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी जनपद पहुंचे। जिला महासचिव आरिफ हबीब ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि राममूर्ति वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जनेश्वर मिश्र को उनके समाजवादी विचारों के प्रति दृढ़ता के कारण श्छोटे लोहियाश की उपाधि मिली थी। उन्होंने कहा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का पुनः संकल्प लेते हैं। लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकारें शैप्स की आड़ में छत्व लागू करने की साजिश रच रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में च्च। (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समाजवादी प्रहरी ऐसा नहीं होने देंगे। आदर्श रहे हैं। उनके विचार हमेशा समाजवादियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प दोहराया।

धूप खिलने से ठंड से लोगों को मिली राहत,दिल के रोगी रखे विशेष ध्यान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में लगातार कई दिनों से धूप निकलने से कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। हालांकि, दिन में तेज धूप के बावजूद शाम को गलन बढ़ रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आर्द्रता 77 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक (।फ) 251 और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इससे एक दिन पहले बुधवार को भी धूप खिली थी, जिससे ठंड से कुछ राहत मिली थी। बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 73 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक (।फ) 215 और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही थी। पिछले दिनों तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई थी। रात में घने कोहरे के चलते बसों और ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे सड़कें सुनसान नजर आ रही थीं। राज्य मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश के कई जिले अभी भी ठंड की चपेट में हैं। उन्होंने आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना जताई है। बदलते मौसम के कारण ठंड लोगों को काफी परेशान कर रही है सुबह और शाम की ठंड के कारण लोगों को ठंड कब लग जा रही है पता ही नहीं चल रहा है जिसके कारण आए दिन लोग विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं ।ठंड के कारण बीमारियों में हार्ट अटैक लकवा सांस फूलने आदि मामले ज्यादातर सामने आ रहे है। वही इन बीमारियों से बचाव और रोकथाम के बारे में जानने के लिए जनपद के वरिष्ठ फिजिशियन और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बी एस उपाध्याय ने हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि ा से गुरुवार को बातचीत के दौरान बताया कि इस समय ठंड से विशेष बचाव की जरूरत है खासकर जो लोग हृदय के रोगी हैं शुगर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष बचाव की जरूरत है इस ठंड में अक्सर ब्लड प्रेशर हाई लो होने पर लकवा और हार्ट प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा हो जाती है। लोगो को गुनगुने पानी का विशेष प्रयोग करें नमक का प्रयोग कम करें व्यायाम पर ध्यान दें बुजुर्ग लोग या 50 वर्ष से ऊपर के लोग जरूरत होने पर ही सुबह उठ और ठंड में बाहर आए संभव हो तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें ।खान पान का विशेष ध यान रखें वसायुक्त सामानों का प्रयोग कम से कम करें मिर्च और मसालेदार सब्जियां और तेल आदि का सेवन ना करें जिससे इन बीमारियों से कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है।

संक्षिप्त खबरें

प्रो. प्रमोद कुमार यादव को अल्ट्रासोनिक सोसायटी ऑफ इंडिया का प्रतिष्ठित "डॉ. एस. पार्थसारथी मेमोरियल अवार्ड" प्राप्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागाध्यक्ष एवं प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिकीय विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के निदेशक प्रो. प्रमोद कुमार यादव को अल्ट्रासोनिक सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित "डॉ. एस. पार्थसारथी मेमोरियल अवार्ड" से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भौतिकी एवं अल्ट्रासोनिक्स के क्षेत्र में गत वर्ष प्रकाशित उनके उत्कृष्ट एवं शोध ापरक कार्य के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मानित शोध कार्य में उनके शोधार्थी प्रशांत श्रीवास्तव सह–लेखक रहे, जिन्हें भी इस उपलब्धि ा में सहभागी बनाया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार चेन्नई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "अल्ट्रासोनिक्स एंड मैटेरियल साइंस फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी" के दौरान प्रदान किया गया। सम्मेलन के अवसर पर प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने आमंत्रित कीनोट वक्ता के रूप में अपने नवीन एवं नवाचारी शोध कार्यों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसे देश–विदेश से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा अत्यंत सराहना मिली। वर्तमान में प्रो. यादव विश्वविद्यालय में भौतिकी विभागाध्यक्ष, प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिक विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के निदेशक तथा अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद पर कार्यरत हैं। उनके कुशल नेतृत्व, अकादमिक दृष्टि एवं शोध ोन्मुख मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को निरंतर नई दिशा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अल्ट्रासोनिक सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाने वाला डॉ. एस. पार्थसारथी मेमोरियल अवार्ड देश के चुनिंदा एवं विशिष्ट वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है, जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रभावशाली योगदान दिया हो। प्रो. यादव को यह सम्मान मिलना न केवल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बल्कि संपूर्ण जौनपुर जनपद के लिए भी गौरव का विषय है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ा पर गुरुवार को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह सहित सभी प्राध्यापकगण ने प्रो. यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वांछित आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैन्ट समर बहादुर सिंह के नेतृत्व मे चौकी जीआरपी अयोध्या धाम थाना जीआरपी ने वांछित आरोपी को उसके घर से दबिस देकर गुरुवार को गिरफ्तार किया।प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट समर बहादुर सिंह ने बताया कि उक्त वांछित आरोपी की पहचान बजरंगी उर्फ महेश बेलदार पुत्र स्व0 दयाराम बेलदार निवासी कुदा केशवपुर दर्शन नगर थाना कोतवाली अयोध्या के रूप में हुई है।वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में चन्द्रमणि पाण्डेय चौकी प्रभारी चौकी जीआरपी अयोध्या धाम थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट व का0 करूणेश पाण्डेय चौकी जीआरपी अयोध्या धाम थाना जीआरपी अयोध्या कैण्ट की सराहनीय भूमिका रही

साइबर ठगी और मानसिक दबाव से बचने के लिए युवा रहें सावधान : डॉ दिग्विजय सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महंत अवेद्यनाथ संगोष्ठी भवन में गुरुवार को "युवा, मानसिक स्वास्थ्य एवं साइबर अपराध" विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को साइबर अपराध ा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना था। यह कार्यक्रम 98 यूपी बटालियन एनसीसी, जौनपुर के तत्वावधान में आयोजित कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंपद्ध 331 के अंतर्गत संपन्न हुआ। इसी क्रम में जनपद पुलिस विभाग द्वारा मेजर ध्यान चन्द्र इनडोर स्टेडियम में साइबर क्राइम एवं यातायात जागरूकता को लेकर संवाद भी किया गया। साइबर अपराध पर आयोजित विशेष व्याख्यान में विश्वविद्यालय के साइबर क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने कहा कि युवाओं के साथ होने वाले साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। एआई के माध्यम से साइबर बुलिंग, फर्जी नौकरी, निवेश के नाम पर ठगी तथा सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों द्वारा साइबर अपराधी युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपराधी व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित विशेष व्याख्यान में विश्वविद्यालय के वेलनेस सेंटर की नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू त्यागी ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन की लगभग 40 प्रतिशत खुशी हमारे अपने हाथों में होती है, लेकिन नकारात्मक सोच के कारण हम स्वयं उसे खो देते हैं। इस अवसर पर जौनपुर जनपद से आए साइबर क्राइम विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराध से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग तथा यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से दी। कार्यक्रम में कैंप कमांडेंट आलोक सिंह धर्मराज सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट विनय कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एनसीसी प्रभारी मनोज पांडे ने किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।